भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं.890

जिसका उत्तर 21.11.2019 को दिया जाना है

वन नेशन - वन फास्ट टैग योजना

890. डॉ॰ सुभाष रामराव भामरेः
श्री कुलदीप राय शर्माः
डॉ॰ अमोल रामसिंह कोल्हेः
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः
श्री ए॰के॰पी॰ चिनराजः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश भर में एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली बनाने हेतु ''वन नेशन - वन फास्ट टैग'' योजना को कार्यान्वित करने का विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं;

(ख) सरकार द्वारा देश भर में विभिन्न टोल प्लाजा पर ट्रैफिक की अधिकता को कम करने के लिए कुल कितने फास्ट टैग जारी किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने फास्ट टैग को जीएसटी ई-वे बिल प्रणाली के साथ जोड़ने के लिए किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है और यदि हॉ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(घ) उक्त पहल के पश्चात लोगों को प्राप्त होने वाले लाभ/फायदों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इसके कार्यान्वयन के पश्चात किसी संभावित कानून और व्यवस्था की समस्या की पहचान और उसका समाधान कर लिया है और यदि हॉ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में फास्ट टैग के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क): जी हां। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (एनईटीसी) कार्यक्रम कवरेज को बढ़ाने और देश भर में उपभोक्ताओं को निर्बाध सेवा प्रदान करने के लिए, भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (आईएचएमसीएल) के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने एनईटीसी कार्यक्रम के तहत राज्य शुल्क प्लाजाओं के समावेशन के लिए योजना आरम्भ किए हैं। एनएचएआई ने कतिपय राज्यों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख): 14.11.2019 तक लगभग 66 लाख फास्टैग जारी किए गए हैं।

(ग) और (घ): जी हां। फास्टैग के साथ ई-वे बिल प्रणाली को एकीकृत करने के लिए आईएचएमसीएल और जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) के बीच 14.10.2019 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह

जीएसटी ई-वे बिल (ईडब्ल्यूबी) प्रणाली को ट्रैक करने और निगरानी करने संबंधी तंत्र में मौजूदा चुनौती को हल करने और इसकी निगरानी में दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है।

(ङ): पायलट आधार पर समर्पित फास्टैग लेन के लिए ट्रायल रन कुछ शुल्क प्लाजाओं पर शुरू हो गया है। एनएचएआई ने सभी शुल्क प्लाजाओं पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। सरकार ने प्रगति की निगरानी के लिए केंद्रीय प्रभारी अधिकारियों को नियुक्त किया है।

(च): देश भर में विभिन्न माध्यमों से विज्ञापन और जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। शुल्क प्लाजाओं और कई अन्य स्थानों पर होर्डिंग्स/बैनर लगाए गए हैं। शुल्क प्लाजाओं के पास पैम्फलेट बांटे जा रहे हैं और शुल्क प्लाजाओं के पास फास्टैग खरीद की सुविधा दी जा रही है।

*****